दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, बुधवार 13 जुलाई 2022 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-04, अंक- 285

महत्वपूर्ण एवं खास

केरल में आरएसएस कार्यालय पर फेंका गया बम, इलाके में दहशत

कन्नूर (आरएनएस)। केरल के कन्नूर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) दफ्तर पर मंगलवार (12 जुलाई) हमला हुआ है। बताया गया कि वहां पर बम फेंका गया, जिसके बाद आसपास अफरा-तफरी फैल गई। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। स्थानीय पुलिस ने बताया, कन्नूर जिला के पय्यनूर में आरएसएस दफ्तर पर बम फेंका गया। यह घटना आज सुबह हुई। वारदात के दौरान इमारत में लगी खिड़कियों के शीशे भी टूट गए। पुलिस ने बताया है कि आगे की जांच जारी है। इस घटना में फिलहाल किसी तरह के जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है।

पुलवामा में जैश-ए-मोहम्मद के शीर्ष आतंकी कोका समेत 2 ढेर, विदेशी राइफल सहित गोला-बारूद बरामद

नई दिल्ली (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यहाँ, पुलवामा जिले में आज सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमे दो आतंकियों ढेर हो गए। बताया जा रहा है कि जिन आतंकियों को ढेर किया उनमें एक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का एक शीर्ष आतंकवादी कैसर कोका भी था। जानकार देते हुए पुलिस के अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ अवंतीपोरा इलाके के वांडकपोरा में सुरक्षा बलों द्वारा घेराबंदी करने और तलाशी अभियान चलाने के बाद शुरू हुई। फिलहाल सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके की घेराबंद कर ली है और तलाशी अभियान चलाया गया है। पुलिस के एक प्रवक्ता ने ट्वीट किया, ''आतंकवादी कैसर कोका को मार गिराया गया। दूसरे आतंकवादी की पहचान की जा रही है। अमेरिका निर्मित एक राइफल (एम-4 कार्बाइन), एक पिस्तौल और सहित अन्य सामग्री, हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया है।'' अधिकारी ने कहा कि कोका आतंकवाद से जुड़ी कई घटनाओं में वांछित था।

सोशल मीडिया पर डमी हथियार के साथ फोटो पोस्ट करने पर दो गिरफ्तार

चूरू (आरएनएस)। सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक पर हथियार के साथ फोटो एडिट कर पोस्ट करने के आरोप में छापर थाना पुलिस ने जोगलिया गांव निवासी दो युवकों अन्नपाल सिंह पुत्र मोहन सिंह (22) एवं दिलीप सिंह पुत्र प्रभु सिंह (18) को गिरफ्तार किया है। चूरू एसपी दिगंत आनंद ने बताया कि आईजी बीकानेर रेंज के निर्देश पर समस्त रेंज में सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों का प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन साइबर क्लीन चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दो युवकों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर अवैध हथियारों के साथ फोटो पोस्ट किए जाने की जानकारी मिलने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगदीश बोहरा एवं सीओ रामप्रताप विश्नोई के सुपरविजन एवं थानाधिकारी जसवीर कुमार के नेतृत्व में थाना छापर से टीम गठित की गई। गठित टीम के हेड कांस्टेबल दशरथ सिंह व अन्य द्वारा दोनों युवकों की पहचान गांव जोगलिया निवासी अन्नपाल सिंह एवं दिलीप सिंह के रूप में की। सोमवार को दोनों युवकों को उनके गांव से शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। एसपी दिगंत आनंद ने परिजनों से अपील की है कि वे अपने बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर लगातार नजर रखें।

हिमाचल प्रदेश में भाजपा को झटका, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष खिमी राम कांग्रेस में शामिल

नई दिल्ली (आरएनएस)। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को आज बड़ा झटका लगा है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष खिमी राम शर्मा मंगलवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। दिल्ली में कांग्रेस का हाथ थामने के बाद राज्य के पूर्व मंत्री और डिप्टी स्पीकर खिमी राम ने कहा कि उन्हें उस पार्टी में शामिल होने पर गर्व है, जिसने देश को आजादी दिलाने में मदद की। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा के प्रति किसी गुस्से के कारण कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहा हूं। मैंने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को आगे ले जाने के लिए सोच-समझकर फैसला लिया है। खिमी राम ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि कांग्रेस राज्य में सरकार बनाने में सक्षम होगी क्योंकि बहुत सारे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और पेंशन योजना से संबंधित कर्मचारियों सहित लंबित कर्मचारी मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि हम इन मुद्दों को राज्य के लोगों के सामने लाएंगे और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने में मदद करेंगे।

गुजरात में भारी बारिश से छह की मौत

अहमदाबाद (आरएनएस)। गुजरात में पिछले तीन दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण बिजली गिरने से छह लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग विस्थापित हो गए। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में राज्य के 14 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। भरूच, छोटाउदपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, डांग, नवसारी और वलसाड जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने पोरबंदर, जूनागढ़, भावनगर, खेड़ा, पंचमहल, दाहोद, आनंद और वडोदरा में भारी बारिश की संभावना जताई है।

पिछले 24 घंटों में नर्मदा जिले के दडियापाड़ा शहर में सबसे अधिक 21 इंच बारिश हुई है, जबकि उमरपाड़ा में 16 इंच, तिलकवाड़ा में 20 इंच, सागबारा में 16 इंच और कपराडा में 15 इंच बारिश हुई है।

आपदा प्रबंधन मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी ने मंगलवार को गांधीनगर स्थित राज्य आपात अभियान केंद्र में आयोजित एक बैठक में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में अब तक छह लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने से हुई हैं। उन्होंने कहा, प्रशासनिक कदाचार या लापरवाही के कारण एक भी मौत की सूचना नहीं है। बचाव कार्यों में नागरिकों का पर्याप्त सहयोग भी मिल रहा है।

मंत्री ने दावा किया कि राज्य प्रशासन नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ की 18 टीमें और एसडीआरएफ की 18 प्लाटून तैनात की गई हैं, जबकि दो टीमों को तैयार रखा गया है।

त्रिवेदी ने कहा कि राज्य के आठ में से तीन जिले भरूच, छोटाउदपुर और नर्मदा रेड अलर्ट जोन से बाहर आ गए हैं, जबकि पांच जिले सूरत, तापी, नवसारी, डांग और वलसाड अभी भी रेड अलर्ट पर हैं।

मंत्री ने कहा कि राज्य में अब तक 27,896 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। इनमें से 18,225 लोग अब भी आश्रय में हैं, जबकि 971 लोग पानी कम होने के बाद घर लौट चुके हैं।

उन्होंने कहा कि बारिश के कारण 15 हाईवे और 439 सडक़ों को वाहनों के आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है।

इस बीच मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हेलीकॉप्टर से राज्य के बारिश प्रभावित इलाकों का दौरा किया। साथ ही उन्होंने बोडेली, राजपीपला और नवसारी के बारिश प्रभावित इलाकों का हवाई निरीक्षण किया।

गुजरात में भारी बारिश के चलते प्रधानमंत्री का 15 जुलाई को राज्य का दौरा रद्द कर दिया गया है।

सीहोर में बाढ़ में फंसे मजदूर, राहत और बचाव कार्य जारी

भोपाल (आरएनएस)। मध्य प्रदेश में हुई बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। निचली बस्तियों में पानी भर गया है तो आवागमन भी बाधित हुआ है। सीहोर जिले में पुलिया पर जलस्तर बढऩे से मजदूर फंस गए हैं, उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य जारी है। आधिकारिक तौर पर मिली जानकारी के अनुसार, सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तहसील के ग्राम सालारोड में एक पुलिया पर अत्यधिक पानी आ जाने के कारण कई मजदूर फंसे हुए हैं। बाढ़ में फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए एसडीईआरएफ के प्लाटून कमांडर अशोक पाटीदार के नेतृत्व में राहत और बचाव कार्य शुरू हो गया है। बताया गया है कि यह मजदूर उस इलाके में थे तभी पानी का जलस्तर बढ़ गया और वे पानी से घिर गए, इन सभी को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू टीम आवश्यक बाढ़ बचाव के उपकरणों के साथ घटनास्थल पर पहुंच रही है। इसी तरह राज्य के कई हिस्सों में भी बाढ़ के हालात बन गए हैं, निचली बस्तियों में पानी भर गया है। बेतवा, ताप्ति और नर्मदा नदी के अलावा छोटी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष भी बनाया है और मदद की खातिर दो टोल फ्री नंबर भी जारी किए हैं।

देश भर में कोरोना के 24 घंटे में 13,615 मामले, 20 मौतें

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोनावायरस के 13,615 नए मामले दर्ज किए गए, जो पिछले दिन की संख्या 16,678 से कम है। इस दौरान देश में 20 और लोगों की मौत कोविड-19 से हुई, जिसके बाद देश में मरने वालों की संख्या 5,25,474 हो गई।

सक्रिय केस भी बढक़र 1,31,043 हो गया है, जो देश के कुल मामलों का 0.30 प्रतिशत है।

पिछले 24 घंटों में 13,265 मरीजों के ठीक होने के बाद ठीक होने वालों की कुल संख्या 4,29,96,427 हो गई। भारत की रिकवरी रेट 98.50 प्रतिशत है।

इस बीच, भारत की दैनिक पॉजिटिविटी दर घटकर 3.23 प्रतिशत हो गई है, जबकि साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 4.24 प्रतिशत है।

देश भर में एक दिन में कुल 4,21,292 टेस्ट किए गए, जिसके बाद कुल संख्या बढक़र 86.73 करोड़ से अधिक हो गई।

मंगलवार की सुबह तक, भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 199 करोड़ से अधिक हो गया, जो 2,61,19,579 सत्रों के माध्यम से हासिल हो पाया।

टीकाकरण अभियान की शुरूआत के बाद से 3.75 करोड़ से अधिक किशोरों को कोविड-19 की पहली खुराक दी गई है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएम केयर्स फंड पर पीएमओ से मांगा जवाब

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत पीएम केयर्स फंड को एक सरकारी फंड घोषित करने की मांग वाली याचिका पर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से विस्तृत जवाब मांगा।

अदालत का यह निर्देश पीएमओ सचिव द्वारा दायर एक पेज के हलफनामे के जवाब में आया है।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने केंद्र से जनहित याचिका (पीआईएल) पर विस्तृत और संपूर्ण जवाब दाखिल करने को कहा।

पीठ ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा, इस तरह के एक महत्वपूर्ण मुद्दे का सिर्फ एक पेज का जवाब?

पीठ ने कहा, हमें एक उचित उत्तर की आवश्यकता है। मुद्दा इतना आसान नहीं है। हमें एक विस्तृत उत्तर की आवश्यकता है।

याचिकाकर्ता सम्यक गंगवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि यह कोष भारत के संविधान के अर्थ में स्टेट (सरकारी) है और संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा बनाए गए किसी भी कोष को संविधान से अनुबंधित नहीं किया जा सकता है।

केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि चार सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल किया जाएगा।

मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी।

अदालत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई थी कि फंड संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत सरकारी है और पीएम केयर्स फंड को अपने नाम/वेबसाइट में प्रधानमंत्री के नाम या उनके हस्ताक्षर का उपयोग करने से रोका जाना चाहिए।

केंद्र के पहले के सबमिशन के अनुसार, पीएम केयर्स फंड आरटीआई अधिनियम की धारा 2 (एच) के दायरे में एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है। केंद्र ने यह भी स्पष्ट किया था कि पीएम केयर्स फंड में कोई भी सरकारी पैसा जमा नहीं किया जाता है और पीएम केयर्स फंड के तहत केवल बिना शर्त और स्वैच्छिक योगदान स्वीकार किए जाते हैं।

इससे पहले पीएमओ द्वारा दायर एक हलफनामे में कहा गया था, यह दोहराया जाता है कि ट्रस्ट का फंड भारत सरकार का फंड नहीं है और यह राशि भारत के समेकित (संयुक्त) कोष में नहीं जाती है।

चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए बैलेट बॉक्स, सामग्री का शुरू किया वितरण

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने मंगलवार को 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए बैलेट बॉक्स और अन्य चुनाव संबंधी सामग्री का वितरण और प्रेषण (डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पैच) शुरू कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार ने ईसी अनूप चंद्र पांडे के साथ यहां निर्वाचन सदन में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के सहायक रिटर्निंग अधिकारी को राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए मतपेटी और अन्य चुनाव संबंधी सामग्री के वितरण और प्रेषण की निगरानी की। दो दिवसीय अभ्यास में, चुनाव सामग्री राज्य विधानसभाओं को भेजी जाएगी, जहां मतदान होगा। राज्य विधानसभाओं के अलावा संसद भवन में भी मतदान होगा। निर्वाचित संसद सदस्य और विधायक राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल का निर्माण करते हैं। संसद और राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं हैं। विधान परिषद के सदस्य (एमएलसी) राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के पात्र नहीं हैं। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव में मतदान कर सकते हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को अपनी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाया है और यशवंत सिन्हा संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार हैं।

राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज रायपुर पहुंचेगी मतदान सामग्री, कड़ी सुरक्षा में विधानसभा स्थित स्ट्रांग-रूम में रखा जाएगा

रायपुर (आरएनएस)। आगामी 18 जुलाई को भारत के 16वें राष्ट्रपति के लिए होने वाले मतदान के लिए नई दिल्ली से निर्वाचन सामग्री 13 जुलाई को रायपुर पहुंचेगी। सहायक रिटर्निंग अधिकारी दिनेश त्रिवेदी और उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार अग्रवाल मतपेटी, मतपत्र एवं अन्य सामग्री लेकर शाम 07:45 बजे के नियमित विमान से माना स्थित स्वामी विवेकानंद विमानतल पहुंचेंगे। दोनों अधिकारियों के साथ राष्ट्रपति चुनाव के लिए उपयोग होने वाली मतपेटी के लिए भी विमान में डिजिग्नेटेड एयर टिकट आरक्षित की गई है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतपेटी की सुरक्षा के लिए उसे चेक-इन-बैगेज में रखने की मनाही है। रायपुर विमानतल पहुंचने पर मतदान सामग्री को राज्य पुलिस के द्वारा एस्कॉर्ट करते हुए विधानसभा भवन स्थित स्ट्रांग-रूम तक सुरक्षित पहुंचाया जाएगा। इन्हें मतदान के लिए निर्धारित तिथि 18 जुलाई तक मतदान प्रारंभ होने के पहले तक स्ट्रांग-रूम में सुरक्षित रखा जाएगा। मतों की गिनती 21 जुलाई को नई दिल्ली में की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 12 जुलाई और 13 जुलाई को मतदान सामग्री के वितरण के दौरान वीडियोग्राफी की जा रही है। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए छत्तीसगढ़ में विधानसभा भवन परिसर में मतदान केन्द्र स्थापित किया गया है जहां राज्य के 90 विधानसभा सदस्यों के लिए मतदान की व्यवस्था की गई है। भारत निर्वाचन आयोग के विशेष अनुमोदन से अन्य राज्यों के निर्वाचक भी इस मतदान केन्द्र में अपना मत डाल सकेंगे। राष्ट्रपति चुनाव के मतदान के लिए राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली एवं प्रत्येक राज्य की राजधानी में मतदान केन्द्र स्थापित किए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सांसदों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र सहित सभी राज्यों के निर्वाचित विधानसभा सदस्य मतदान करते हैं।

कपड़े की आड़ में दुबई से लाई गई 350 करोड़ रुपए की हेरोइन, एटीएस ने किया जब्त

गांधीनगर (आरएनएस)। गुजरात एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एटीएस ने गुजरात के मुंद्रा पोर्ट में करीब 70 किलो हेरोइन पकड़ी है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कुल कीमत 350 करोड़ रुपये बताई जा रही है। एटीएस को सूचना मिली थी कि सोमवार देर शाम कच्छ के मुंद्रा सीएफएस पर कंटेनर पहुंचा है, जिसके बाद एटीएस ने कार्रवाई करते हुए हेरोइन को जब्त की है। पुलिस सूत्रों ने कहा कि एटीएस मुंद्रा बंदरगाह पर नशीले पदार्थों के भंडार के बारे में एक इनपुट के आधार पर राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के साथ एक अभियान चला रही है।

सूत्रों के अनुसार, बताया जा रहा है कि कि कपड़े की आड़ में ड्रग्स की तस्करी की जाती थी, जिसे कंटेनर के जरिए दुबई के जेबेल अली बंदरगाह से लाया गया था। एक एटीएस अधिकारी ने बताया कि मुंद्रा बंदरगाह पर नशीली दवाओं की जब्ती के लिए एक अभियान जारी है। जब तक हम दवाओं की गुणवत्ता और मात्रा की जांच नहीं कर लेते, तब तक हम इस ऑपरेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन इस बात की पुष्टि हो गई है कि ड्रग्स की बरामदगी हुई है।

बता दें कि इससे पहले अप्रैल महीने में भी गुजरात एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की थी। एटीएस और डीआरआई ने कच्छ के कांडला बंदरगाह पर एक कंटेनर में छुपाकर रखे गए 1300 करोड़ रुपये मूल्य की 260 किलोग्राम हेरोइन जब्त की थी।

उत्तराखंड : सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया नई शिक्षा नीति-2020 का आगाज, देश का बना पहला राज्य

देहरादून (आरएनएस)। उत्तराखंड में 12 जुलाई यानी आज से नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। राज्य में सर्वप्रथम विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत प्राइमरी एजुकेशन में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को शुरू किया गया है। विद्यालयी शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी पहले ही पूरी कर ली थी। शिक्षा महानिदेशालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बालवाटिकाओं का उद्घाटन कर सूबे में नई शिक्षा नीति का औपचारिक रूप से विधिवत शुभारंभ किया।

देश का बना पहला राज्य- इसके साथ ही उत्तराखंड एनईपी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य के समस्त जनपदों में विकासखंड स्तर पर चिन्हित को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केन्द्रों में वृहद रूप से बालवाटिकाओं का क्षेत्रीय विधायक एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि उद्घाटन करेंगे। जिसमें शिक्षाविद्, अभिभावक एवं छात्र-छात्राएं शामिल होंगे।

शिक्षा मंत्री ने क्या कहा- शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य में बीस हजार से अधिक आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। जिसमें से प्रथम चरण में शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में संचालित पांच हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों में एनईपी के तहत बालवाटिका कक्षाओं का संचालन शुरू किया जायेगा। उन्होंने बताया कि सूबे में 20 हजार 67 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं, जिसमें से 20 हजार 17 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं, जिनमें 14,555 आंगनबाड़ी वर्कर्स तैनात हैं।

बच्चों को पढ़ाया जायेगा एनईपी के प्रावधानों के तहत- इसके अलावा आंगनबाड़ी केन्द्रों में 14,249 सहायिकाएं एवं 4,941 मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नियुक्त हैं। डॉ. रावत ने बताया कि राज्य में प्री-प्राइमरी स्तर पर बालवाटिकाओं में बच्चों को एनईपी के प्रावधानों के तहत पढ़ाया जायेगा। जिसके लिये पाठ्यक्रम तैयार कर लिया गया है। शिक्षा मंत्री धन सिंह ने बताया कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं शिक्षकों के लिये हस्तपुस्तिका, बच्चों के लिये तीन अभ्यास पुस्तिका स्वास्थ्य, संवाद एवं सृजन तैयार की गई हैं।

रावत ने बताया कि सूबे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू किये जाने को लेकर विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि बालवाटिका कक्षाओं के शुभारम्भ अवसर पर मुख्यमंत्री के द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय के नव निर्मित भवन का लोकार्पण किया जायेगा। इसके साथ ही एससीईआरटी (स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग) के भवन का शिलान्यास भी किया जायेगा। उन्होंने आगे बताया कि कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिये विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं।

नई शिक्षा नीति 2020- भारत सरकार ने नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आरंभ की है। जिसके अंतर्गत सरकार ने एजुकेशन पॉलिसी में काफी सारे मुख्य बदलाव किए हैं। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। अब मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। नेशनल एजुकेशन पालिसी के अंतर्गत 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100 प्रतिशत जी ई आर के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय तक शिक्षा का सार्वभौमीकरण किया जाएगा। पहले 10 प्लस 2 का पैटर्न फॉलो किया जाता था। परंतु अब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 5 प्लस 3प्लस 3 प्लस 4 का पैटर्न फॉलो किया जाएगा। यह नेशनल एजुकेशन पोलिसी 2014 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र में शामिल था।

एमवाईएनईपी 2020 प्लेटफॉर्म का शुभारंभ- तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा एनसीटीई प्लेटफार्म पर एमवाईएनईपी 2020 प्लेटफार्म लांच किया गया था। यह प्लेटफॉर्म 1 अप्रैल 2021 से लेकर 15 मई 2021 तक कार्यशील रहा था। इस प्लेटफार्म के माध्यम से नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर एवं नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग प्रोग्राम में बरशिप के विकास के लिए ड्राफ्ट तैयार किया गया था। इस प्लेटफार्म के माध्यम से सभी हितधारकों से ड्राफ्ट के लिए सुझाव, इनपुट तथा सदस्यता आमंत्रित की गई थी। इन हितधारकों में शिक्षक, शिक्षा पेशेवर, शिक्षाविद एवं अन्य शिक्षा से संबंधित हितधारकों को शामिल किया गया था।